

भारत का सहकारिता क्षेत्र

प्रलिस के लयि:

[सहकारिता क्षेत्र, प्राथमिक कृषि ऋण समतियिँ, बहु-राज्य सहकारी समतियिँ अधनियिम, 2002, 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधनियिम, 2011, बहु-राज्य सहकारी समतियिँ \(संशोधन\) अधनियिम, 2022, इफको।](#)

मेन्स के लयि:

भारत में सहकारिता क्षेत्र की स्थिति, भारत में सहकारिता समतियिँ के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियिँ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वशिव की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जिसका शुभारंभ वर्तमान में 11 राज्यों की 11 [प्राथमिक कृषि ऋण समतियिँ](#) में किया गया है।

- यह [सहकारिता क्षेत्र](#) में एक महत्त्वपूर्ण विकास को दर्शाता है।

अनाज भंडारण योजना से संबंधित वशैषताएँ क्या हैं?

- **परचिय:** अनाज भंडारण योजना का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में ₹1.25 लाख करोड़ के निवेश के साथ **700 लाख टन भंडारण क्षमता** स्थापित करना है।
 - इस परियोजना में भारत सरकार की वभिन्न मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करवकिंदरीकृत गोदामों, कसटम हायरगि सेंटरों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित PACS के स्तर पर कृषि बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना शामिल है।
- **अपेक्षित परिणाम:** इस परियोजना के माध्यम से किसान PACS गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करने में, अगले फसल चक्र के लिये ब्रजि फाइनेंस की पेशकश करने अथवा संकटपूर्ण अवधि के दौरान MSP पर फसल का विक्रय करने में सक्षम होंगे।
 - अनाज के भंडारण क्षमता में वृद्धि करने से फसल के बाद होने वाले नुकसान में कमी आती है, किसानों की आय में सुधार होता है और ज़मीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है।

भारत में सहकारिता क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- **परचिय:** सहकारी समतियिँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिये किया जाता है।
 - कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और मत्स्य पालन जैसे वभिन्न क्षेत्रों में **800,000 से अधिक सहकारी समतियिँ** के साथ भारत का सहकारिता नेटवर्क वशिव के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है।
- **भारत में सहकारिता क्षेत्र का विकास:**
 - **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56):** व्यापक सामुदायिक विकास के लिये सहकारी समतियिँ को बढ़ावा दिया गया।
 - **बहु-राज्य सहकारी समति अधनियिम, 2002:** बहु-राज्य सहकारी समतियिँ के गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान करता है।
 - वर्ष 2011 का **97वाँ संवैधानिक संशोधन अधनियिम:** सहकारी समतियिँ के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया (**अनुच्छेद 19**)।
 - सहकारी समतियिँ पर राज्य की नीति का एक **नया नदिशक सदिधांत प्रस्तुत किया गया (अनुच्छेद 43-B)**।
 - संवैधान में "**सहकारी समतियिँ**" शीर्षक से एक नया भाग **IX-B** जोड़ा गया (**अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT**)।
 - **बहु-राज्य सहकारी समतियिँ (MSCS)** को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिये संसद को अधिकार दिया गया और साथ ही अन्य सहकारी समतियिँ के लिये राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा गया।

- **केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना (2021):** सहकारी मामलों की ज़म्मेदारी संभाली गई, जिसकी देख-रेख पहले कृषि मंत्रालय करता था।
- **बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) अधिनियम, 2022:** इसका उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों हेतु वनियमन बढ़ाना है।
 - बहु-राज्य सहकारी समितियों में बोरड चुनावों की नगिरानी हेतु **सहकारी चुनाव प्राधिकरण की शुरुआत** की गई।
 - बहु-राज्य सहकारी समितियों को अपनी **शेयरधारिता को भुनाने से पहले सरकारी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता** होती है।
 - संघर्षरत लोगों को पुनर्जीवित करने के लिये लाभदायक बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा वित्त पोषित **एकसहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की स्थापना** का आह्वान किया गया।
 - राज्य सहकारी समितियों को राज्य कानूनों के अधीन मौजूदा **बहु-राज्य सहकारी समितियों में वलिय करने की अनुमति** देता है।
- **भारत में सहकारी समितियों के उदाहरण:**
 - **प्राथमिक कृषि साख समितियाँ:** वे अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की ज़मीनी स्तर की शाखाएँ हैं।
 - यह एक ओर **अंतिम उधारकर्ताओं (किसानों)** और दूसरी ओर उच्च वित्तपोषण एजेंसियों अर्थात् **अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों** तथा **RBI** एवं **नाबारड** के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करता है।
 - **अमूल (आनंद मलिक यूनिवर्सिटी लमिटेड):** एक डेयरी दूधगज और भारत की श्वेत क्रांति में अग्रणी, अमूल गुजरात में लाखों दूध उत्पादकों का एक संघ है। इसकी सफलता ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया।
 - **भारतीय किसान उर्वरक सहकारी:** विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समितियों में से एक, IFFCO पूरे भारत में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और कृषि सामग्री/नविषि्टा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - **बागवानी उत्पादक सहकारी वपिणन और प्रसंस्करण सोसायटी (HOPCOMS):** किसानों के लिये उचित रटिर्न सुनिश्चित करने वाले कृषि उपज आउटलेट के अपने नेटवर्क के लिये प्रसिद्धि है।
 - **लज्जत पापड (श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड):** पापड (भारतीय दाल से निर्मित) उत्पादन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक प्रेरक महिला सहकारी संस्था है।

नोट: बंगाल सचिवालय सहकारी समिति बनाम आलोक कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में संसद और राज्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधानमंडलों को उचित कानून बनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा।

भारत में सहकारी समितियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संचालन और प्रबंधन के मुद्दे:**
 - **सीमिति व्यावसायिकता:** कई सहकारी समितियों में पेशेवर प्रबंधन संरचनाओं का अभाव है, जो अकुशल संचालन और नरिणायक क्षमता का कारण है।
 - **राजनीतिक हस्तक्षेप:** सहकारी समितियों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी स्वायत्तता को कमज़ोर करता है और सदस्यों के हितों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है।
- **पूंजी और संसाधन बाधाएँ:**
 - **अपर्याप्त फंडिंग:** सहकारी समितियाँ प्रायः **वसितार, आधुनिकीकरण** और नए उद्यमों के **विकास** हेतु पर्याप्त पूंजी तक पहुँचने के लिये संघर्ष करती हैं।
 - **सीमिति बुनियादी ढाँचा:** उचित भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और बाज़ार संबंधों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सहकारी समितियों की वृद्धि तथा प्रतस्पर्द्धात्मकता में बाधा बनती है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:**
 - **कम जागरूकता और भागीदारी:** संभावित सदस्यों के बीच सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमिति करती है।
 - **सामाजिक असमानताएँ:** कुछ मामलों में, सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित विभाजन सहकारी समितियों के भीतर समान भागीदारी एवं प्रतनिधित्व के लिये बाधाएँ पैदा करते हैं।

भारत में सहकारी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** मूल्य शृंखला को मज़बूत करने और **सहकारी उत्पादों के लिये बाज़ार पहुँच बढ़ाने हेतु** गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं एवं प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
 - साथ ही, सहकारी संचालन और प्रबंधन की दक्षता में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **नवाचार हब के रूप में सहकारी समितियाँ:** सहकारी समितियों की धारणा को पारंपरिक और ग्रामीण से पृथक करप्रयोग तथा **नवाचार के केंद्रों में हस्तांतरित** करने की आवश्यकता है।
 - साथ ही, अत्याधुनिक कृषि तकनीकों के साथ कार्य करने वाली सहकारी समितियों और **नवीकरणीय ऊर्जा** पर ध्यान केंद्रित करने को उजागर करने की भी आवश्यकता है।
- **सहकारी "प्रभावक":** इसमें युवा, तकनीक-प्रेमी सहकारी सदस्यों को वकील और वचिरक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में पहचानना और उनका पोषण करना, **सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों** के माध्यम से सहकारी समितियों की छवि को परवितरित करना शामिल है।
- **सहकारी त्वरण क्षेत्र:** विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को सहकारी त्वरण क्षेत्र के रूप में नामित करना, जहाँ नयियों में **अस्थायी रूप से शथिलिता प्रदान की जाती है** और नवीन व्यापार मॉडल के साथ विविध सहकारी प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है।
- **सहकारी नेतृत्व वाली पर्यटन पहल:** ग्रामीण क्षेत्रों में **सहकारी संचालित इको-पर्यटन** और समुदाय-आधारित पर्यटन पहल का विकास करना,

जससे यात्रियों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं तथा आजीविका का अनुभव करने की अनुमति मिल सके।

- इसमें पर्यटन गतिविधियों को सामूहिक रूप से प्रबंधित करने, आय उत्पन्न करने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषिवित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषिवित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को कनि बाधाओं और कसोटियों का सामना करना पडता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का कसि प्रकार उपयोग कया जा सकता है?" (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-cooperative-sector>

